POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 07 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश की आधी आबादी का विकास के मुद्दों में यदि सहयोग नहीं मिलता है, तो विकास की दर कम हो जाती है। यह तथ्य सर्वमान्य है और इसे अर्थशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य ने भी स्वीकार किया था। अतः इन्हें विकास की धारा से जोड़े बिना खुशहाली नहीं आ सकती।

इसी मद्देनजर, देश में 80 के दशक के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा उनके सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम बने। महिला संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक महिला जागृति का बिगुल बजा।

एक ओर पंचायती राज व्यवस्था में मिले 50 फीसदी आरक्षण से महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त बनकर, कई योजनाओं के जरिए गांव की भलाई और ग्रामीणों को लाभान्वित करने में आगे आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ, गांव-गांव में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों ने भी महिलाओं को घर की चौखट से बाहर आने का न्योता दिया है।

समूह की महिलाएं अपनी छोटी-छोटी बचत तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ऋण योजनाओं व अन्य बैंक ऋणों से स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। समूह की महिलाएं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हैं और गांवों में फैली कुरीतियों को दूर करने और गांव के विकास में संगठित रूप से सहयोग दे रही हैं।

समूहों की महिलाएं ऐसे हुई लाभान्वितः

- महिलाओं को बैंक से ऋण मिला।
- उनका आत्मविश्वास बढ़ा।
- उन्हें समूह संगठन का फायदा दिखा।
- उनका घर-परिवार में सम्मान बढ़ा।
- धीरे-धीरे समूह सशक्त होता गया।
- बैकों व नाबार्ड जैसी संस्थाओं का उन पर विश्वास जमा।
- महिलाएं नए-नए रोजगार पाने को आगे आने लगी और कारवां बनता गया।

महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन

गांवों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से आज सभी वाकिफ हैं। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से संचालित यह कार्यक्रम काफी सफल माना जा रहा है। गांवों में 10 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह गठित करती हैं और समूह में से पदाधिकारियों का चुनाव करती हैं।

कई सरकारी, गैर सरकारी व स्वैच्छिक संगठन या बैंक ऐसे समूहों का गठन कर उनको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे उन्हें समूह संचालन के तौर-तरीकों से परिचित कराते हैं एवं उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। महिलाएं अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा कर समूह में एकत्रित करती हैं। जिसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है।एकत्रित राशि बैंक में जमा कराई जाती है। समूह की महिलाएं बैंकों व नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। जब किसी सदस्य महिला को किसी व्यक्तिगत काम या रोजगार के लिए ऋण की जरूरत होती है, तो उसे बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस पर समूह से जुड़ी महिलाएं ही निर्णय लेती हैं। बैंक से लिया गया ऋण निर्धारित किश्तों में वापस जमा कराया जाता है।

समय के साथ परिवर्तन के लिए तैयार

कमर तक लटकते घूंघट से जमीन पर अपनी आंखे गडाए हुए अपनी जिन्दगी की गाड़ी को खींचने वाली ग्रामीण महिलाएं अब समय के साथ-साथ अपने आप में परिवर्तन लाने को तैयार हैं। वे अब सामाजिक रूढ़िवादी विचारों, परम्पराओं व कुरीतियों को त्याग कर समाज व खुद के विकास का रास्ता तय करती हैं। इससे उनके विकास और स्वावलम्बन की दिशा में कदम बढ़े हैं।

'कट्स' मानव विकास केन्द्र द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह अपनी छोटी-छोटी बचतों से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बूंद-बूंद से भरा घड़ा इतना छलक उठेगा। वे अपने सपनों को साकार करने और स्वावलम्बन की योजनाएं सामूहिक रूप से मिल बैठ कर तय करती हैं। संस्था के कार्यकर्ता उनके मकसद को पूरा करने को सक्रिय हैं।

आत्म निर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम

देश समाज और परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना आवश्यक है। इससे न केवल खुशहाली आएगी, बल्कि समाज व परिवार में महिलाओं का महत्व भी बढ़ेगा। इस सोच के साथ 'कट्स' मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 1993 में महिला सशक्तिकरण परियोजना की शुरुआत की गई।

इस दौरान यह महसूस किया गया कि ग्रामीण समाज में मौजूद पर्दाप्रथा, दहेज, बालविवाह और महिला हिंसा जैसी अनेक कुरीतियां महिलाओं को पीछे की ओर धकेल रही है। सबसे बड़ी समस्या गरीबी और अशिक्षा है। इसके चलते घर परिवार में काम के बोझतले दबे होने के बावजूद महिलाओं को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार तक नहीं है।

ऐसे कई मुद्दों व समस्याओं पर विचार-विमर्श कर संस्था ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन का निर्णय लिया।

भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय स्वयं सहायता समूह सम्मेलन

ग्रामीण विकास का आधार है स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास का आधार है। महिलाएं समूह से जुड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने व आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए तत्पर है।

यह बात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक जी.जी. माम्मेन ने भीलवाड़ा में कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा 5 जून को आयोजित जिला स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव व कट्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष मीठा लाल मेहता ने कहा कि महिलाएं संगठित होकर आर्थिक रूप से सबल बनें और गांव के विकास में भी अपना योगदान दें। इस अवसर पर कट्स के महामंत्री प्रदीप महता ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनने की प्रेरणा दी। नाबार्ड के महाप्रबन्धक आर.एस.जोधा ने नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर समूह गठन और महिला विकास में श्रेष्ठ काम के लिए मंजू पाराशर, विनोद कंवर, मंजू राव, सीमा तिवाड़ी, तारादेवी तम्बोली को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में जिले की मण्डलगढ़, सुवाणा, बनेड़ा आदि पंचायत समिति क्षेत्रों में गठित 400 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 350 महिलाओं ने भाग लिया।

समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है। ऐसे समूहों का गठन करना तो आसान है, लेकिन उसे आगे तक ले जाना मुश्किल होता है। जरूरी यह है कि समूह का स्थायीत्व बना रहे और उनकी निरन्तरता कायम रहे।

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर रवि जैन ने यह विचार कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा 6 जून को चित्तौड़गढ़ में आयोजित जिला स्तरीय स्वयं सहायता समूह सम्मेलन मे व्यक्त करते हुए कहा कि कट्स संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में काफी सराहनीय कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने जिले के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्य सचिव व कट्स इन्टरनेशनल के अध्यक्ष मीठालाल मेहता ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। समूह की महिलाएं संगठित होकर गांव की स्वास्थ-सुरक्षा तथा अन्य समस्याओं के निराकरण व गांव के विकास में भी भागीदार बने। नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक पंकज यादव ने समूहों के लिए नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम में कट्स के महामंत्री प्रदीप महता ने समूह की महिलाओं को समाजिक जागृति लाने और गांव के विकास में काम करने को कहा। सम्मेलन में आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधक बृज बाहेती, यूनिसेफ के प्रतिनिधि व जिले के विभिन्न गांवों से आई समूहों की करीब300 महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया।

समूहों को मिली सफलता से बढ़ा नेटवर्क

आखिर प्रयास रंग लाए। नतीजतन अब चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों में 800 स्वयं सहायता समूह हैं। इन समूहों से 9000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वे बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने लगी हैं। वे माहवार अपनी आमदनी से छोटी-छोटी बचत कर समूह के माध्यम से बैंक में जमा कराती हैं। इन समूहों की नियमित बैठकें आयोजित होती हैं और बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण लिखा जाता है।

समूहों की महिलाएं अब घर से बाहर निकल कर बैंक शाखाओं में जाती हैं और बैंकों की विभिन्न योजनाओं से लाभ लेकर परिवार की कुल आमदनी में अपना योगदान देने लगी हैं। वे अपने घरों में घरेलू उद्योग चला रही हैं और नये-नये काम धंधों को बढ़ाने की दिशा में भी अग्रसर हो रही हैं।

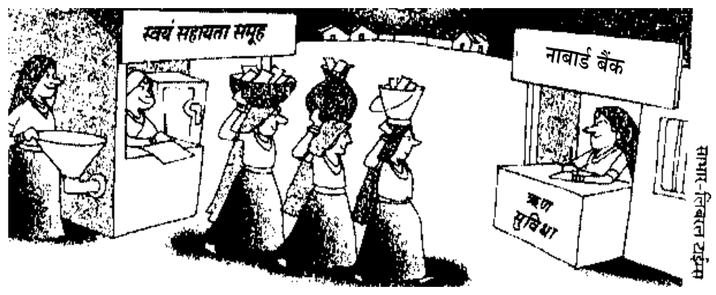

समूह के माध्यम से मिले रोजगार

बैंक ऋण के साथ-साथ महिलाओं ने विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेकर नये-नये रोजगार तलाशना शुरू किया है और रोजगार गतिविधियों में दक्षता के लिए प्रशिक्षण लेकर काम धंधे शुरू किए हैं।

स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समूह की महिलाएं रेडिमेड कपड़ों की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, कच्चा घाणी तेल, सिलाई व कशीदाकारी, किराणा दुकान, कपड़े के बैग बनाना, दरियां व गलीचे बनाना, आयुर्वेदिक व हर्बल तेल-क्रीम व अन्य उत्पाद बनाना, आर्टिफिसियल ज्वैलरी तैयार करना, हैण्डीक्राफ्ट सामान, सोफ्ट टॉयज बनाना,पशु पालन को बढ़ावा देना एवं दुग्ध व्यवसाय जैसे कई काम धंधों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

महिला समृद्धि केन्द्रों की होगी स्थापना

मुख्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का गठन महिला सशक्तिकरण का आधार है। राज्य में दो लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं, जिनमें 20 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार चाहती है कि समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से और ज्यादा सबल बनें।

इस कार्यक्रम को और मजबूती देने के लिए प्रत्येक जिले के एक-एक ब्लॉक में धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्थापित होंगे। जिनके माध्यम से महिलाओं को गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था की जाएगी।

कर्ज जुटाना होगा आसान

पिछले केन्द्रीय बजट में महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधि का सृजन किया गया था। इस साल के बजट में इस निधि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अब स्वयं सहायता समूह बना कर काम करने वाली महिलाओं के लिए बैकों से कम लागत पर कर्ज जुटाना आसान हो जाएगा।

समूहों को बैंकों से सात फीसदी सालाना दर से कर्ज मिलेगा। समय पर ऋण चुकाने पर तीन फीसदी ब्याज माफ हो जाएगा। अर्थात उन्हें चार फीसदी ही ब्याज देना होगा। ब्याज दरों की यह सीमा तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर मिलेगी। इस ऋण से समूह की महिलाएं कोई घरेलू उद्योग लगा कर आत्मनिर्भर हो सकती है। फिलहाल पहले चरण में यह सुविधा देश के 150 जिलों के 600 ब्लॉक्स में दी जाएगी।

नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने किसानों की सुविधा और उनके लिए कार्ड की अहमियत बढ़े इसके लिए नई किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी की है।

इस कार्ड योजना को लागू करने और इसकी सुविधाएं किसानों को दिलाने के लिए नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों और सभी सहकारी बैंकों को कार्ड के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस योजना के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता पांच साल के लिए होगी। सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सामान्य आकलन के साथ फ्लैक्सी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्थाा होगी।

किसान क्लब कार्यक्रम

नाबार्ड द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कृषि उत्पादन तथाा उत्पादकता बढ़ाने के लिए बैंक ऋण तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से किसान क्लबों की परिकल्पना भी की है। किसान इस कार्यक्रम से फायदा उठा सकते है।

आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण

समूह कार्य से जुड़कर महिलाएं घर परिवार और गांव में अपनी पहचान बनाने लगी हैं। महिलाओं के एकजुट करने में भी समूह कारगर साबित हो रहे हैं। वे गांव की स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सदा तैयार रहती हैं और सामूहिक रूप से उच्चाधिकारियों से मिल कर समस्याओं के हल में अपना योगदान देती है। अपने क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, लिंग भेद, नशामुक्ति, महिला हिंसा व अशिक्षा को मिटाने में समूह अच्छी पहल कर रहे हैं।

समूहों के माध्यम से चले कार्यक्रम

ग्रामीण स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा संगठन तैयार हो चुका है। समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक सरोकार के अन्य मुद्दों पर प्रभावी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। जल संरक्षण और गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू कर उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। महिला समूहों के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

भ्रष्टाचारियों का बचाव क्यों?

ग्राम गदर में पढ़ा कि भ्रष्टाचार और काली कमाई पर नियंत्रण की मंशा जताते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012 पारित कराया है। विधेयक में लोकसेवकों द्वारा गलत तरीकों से कमाई सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है।

इससे आमजन को लगने लगा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठा रही है। लेकिन अनुभवी लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अब तक बने ढेरों कानूनों का खुद सरकार पालना नहीं करना चाहती। वह भ्रष्टाचारी राजनेताओं और बड़े अधिकारियों पर जानते बूझते कार्रवाई क्यों नहीं करती? दोषी होने पर भी उनके बचाव में क्यों रहती है?

- कमलेश्वर गौड़, श्रीमाधोपुर, सीकर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर